

न्यायालय, सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सीवर, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 334/2019(258/2018)

GCMS NO. : 2018/00135

अपीलान्ट :-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. बगदाराम पुत्र चुन्नाराम<br/>जाति- रेगर, निवासी- गिरी,<br/>तहसील रायपुर जिला-<br/>पाली(राज0) हाल निवासी<br/>औधौगिक क्षेत्र पुलिस थाना,<br/>सरदार समन्द रोड़, 433<br/>सोसायटी नगर पाली, तहसील व<br/>जिला- पाली(राज0)</p> | <p>1. सांवलराम पुत्र चूनाराम<br/>2. केलकी पत्नि अल्पूराम<br/>3. लाबूराम पुत्र संग्राम<br/>4. घेवरराम संग्राम फौत<br/>कौम- जटिया, निवासी- गिरी,<br/>तहसील- रायपुर जिला-<br/>पाली(राज0)<br/>5. तहसीलदार, जैतारण<br/>6. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण<br/>7. पटवारी, पटवार हल्का टूंकड़ा<br/>8. दलपत कुमार पुत्र मोहनलाल नायक<br/>R/O भमेरिया जिला प्रतापगढ़(राज0)</p> |
|--|--|

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. एवं धारा 05 म्याद अधिनियम

तारीख रजू 27/09/2018

- उपस्थित:-
1. श्री किशोरकुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
  2. श्री सुरेश चौधरी, श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी।


-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 19/03/2021

वकील प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि राजस्व मौजा ग्राम टूंकड़ा, पटवार हल्का टूंकड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक रास, तहसील- जैतारण जिला- पाली में खसरा नम्बर 211, 213, 215 रकबा क्रमशः 17 बीघा 04 बिस्वा, 01 बीघा 15 बिस्वा व 02 बीघा 07 बिस्वा किरम बरानी दोयम की आई हुई है। जिसका उपयोग उपभोग वादी अपने पिता प्रपिता के समय से करता आ रहा है एवं काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करके दिनांक 18.05.1975 को म्युटेशन संख्या 114 गलत करवा दिया। जिसमें वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया, जिस हेतु वादी को जानकारी होने पर वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर साहब के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी एक विकलांग व गरीब व्यक्ति है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है व वादी अक्सर बिमार रहता है तथा वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 30.06.2016 को राजस्व केम्प की कोई जानकारी वादी को नहीं दी एवं न ही वादी राजस्व केम्प में हाजिर हुआ है एवं वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करके वादपत्र को खारिज करवा दिया। जबकि वादी को इस बाबत कोई सूचना या ईत्तला नहीं दी गई। वादी ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका प्रकरण खारिज हो गया है, तब वादी ने दिनांक 11.09.2018 को प्रकरण की नकलें प्राप्त की तब जानकारी हुई कि मुझे वादी के अधिवक्ता ने मुझे बिना जानकारी दिये एवं मेरी अनुपस्थिति में मेरा वादपत्र खारिज करवा दिया गया है। इस हेतु वादी को कोई

जानकारी नहीं गई है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का हित निहित है। इसलिए वादपत्र को रेस्टोर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी द्वारा नकलें दिनांक 11.09.2018 को प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष अन्दर म्याद पेश किया जा रहा है तथा म्याद प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि- वादी का वादपत्र रेस्टोर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे, ताकि वादी को न्याय मिल सकें। प्रार्थी/वादी ने साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम का पेश किया जो सा0मि0 है तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम में कथन किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करके वादपत्र को खारिज करवा दिया। जबकि वादी को इस बाबत कोई सूचना या ईत्तला नहीं दी गई। वादी ने जब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका प्रकरण खारिज हो गया है, तब वादी ने दिनांक 11.09.2018 को प्रकरण की नकलें प्राप्त की तब जानकारी हुई कि- मुझे वादी के अधिवक्ता ने मुझे बिना जानकारी दिये एवं मेरी अनुपस्थिति में मेरा वादपत्र खारिज करवा दिया गया है। इस हेतु वादी को कोई जानकारी नहीं गई है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का हित निहित है इस पर वादी द्वारा नकलें दिनांक 11.09.2018 को प्राप्त की है, इसलिए खारिज की दिनांक 30.06.2016 से दिनांक 11.09.2018 के समय को कण्डोन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किया जावे। इस बाबत यह प्रार्थना पत्र सादर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 30.06.2016 से दिनांक 11.09.2018 के समय को कण्डोन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करावे।।

प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी विरुद्ध प्रतिवादीगण ने जवाब पेश किया जो सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 01 लाबूराम पुत्र संग्राम ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि दरखास्त का फिकरा नम्बर 1 कतई गलत व नामंजूर है। ग्राम टूंकड़ा तहसील जैतारण की सीमा में स्थित ख0नं0 211, 213, 215 की आराजी कुल रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा वादी/प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की नहीं है। बल्कि. प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। दरखास्त का फिकरा नम्बर 2 का जबाब है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का म्युटेशन संख्या 114 माफिक कानून के भरा गया है जो नहीं म्युटेशन किसी तरह से गलत नहीं है। वादी/प्रार्थी ने केवल मात्र दावा दायर करने की गरज से उक्त म्युटेशन को गलत अवैध बताकर दावा पेश किया है जो दावा खारिज हो चुका है। उक्त म्युटेशन वैध है व कानूनी प्रावधानों के तहत भरा गया है। दरखास्त के फिकरा नम्बर 3 का जबाब है कि दिनांक 30/06/2016 को राजस्व कैम्प होना राज्य सरकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की आम सूचनाएं दैनिक अखबार, टी.वी. से व प्रचार प्रसार हर गांव में की गयी थी। वादी ने यह आवेदन पेश करने हेतु झूठा आधार बताया कि उसके अधिवक्ता ने उसे कैम्प की सूचना नहीं दी। दिनांक 30/06/2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प टूंकड़ा में वादी के अधिवक्ता स्वयं ने उपस्थित होकर इस वाद को नोटप्रेस में खारिज करवाया है, इसलिए वादी अपने अधिवक्ता के कृत्य से कानूनन पाबन्द है और कानून का भी यह सिद्धान्त है कि अपने अधिवक्ता को जो जानकारी है, वही पक्षकार को भी होती है। वादी का वाद दिनांक 30.06.2016 को खारिज हुआ व रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 17.09.2018 को दो वर्षों के वाद पेश किया, वाद खारिज का आदेश अन्तिम हो चुका है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। वादी का यह कानूनी कर्तव्य था

  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) जैतारण

कि वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखे तथा अपने वाद की पैरवी हेतु समय समय पर जानकारी प्राप्त करे। ऐसा नहीं करना वादी का कानून की निगाह में गौर लापरवाही है, इसलिए वादी स्वयं अपनी लापरवाही का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। वादी ने दिनांक 11/09/2018 को उक्त वाद खारिज होने की जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर यह आवेदन आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पेश करना बताया है, इस सम्बन्ध में वादी ने अपने अधिवक्ता से किस दिन सम्पर्क हुआ, दावा खारिज की जानकारी कब हुई तथा किस माध्यम से वादी को जानकारी हुई कोई उल्लेख नहीं किया तथा न ही वादी ने बताया है इसलिए वादी ने जो यह आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का आवेदन पेश किया है व इसमें जो कारण बताये हैं, वो कानूनन कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है तथा खादी की गौर लापरवाही है इसलिए उचित व पर्याप्त कारण के आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का आवेदन पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। वादी का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतु उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नहीं बताया है। इसलिए वादी किसी भी तरह से उक्त वाद रेस्टोर करवाने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। "Suit dismissed-As "Notpressed" is not-The Same as Advocate pleaded-"No Instruction"- It not press amount to "With drow of Suit" therefore 09 R04 CPC not maintainable" अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि जबाब प्रार्थनापत्र में दर्ज आधारों एवं कानूनी प्रावधानों के तहत वादी कानूनी रूप से उक्त वाद रेस्टोर करवाने का हकदार नहीं है वादी का आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थनापत्र उपरोक्त आधारों से पोषणीय नहीं होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 लाबूराम पुत्र संग्राम ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 05 म्याद अधिनियम का जवाब प्रार्थना पेश करते हुये कथन किया है कि दरखास्त के फिकरा नम्बर 1 में दर्ज तमाम कथन झूठे आधारहीन व कतई गलत होने से नामंजूर है। दिनांक 30/06/2016 को राजस्व कैम्प होना राज्य सरकार का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम की आम सूचनाएँ दैनिक अखबार, टी.वी. से व प्रचार प्रसार हर गांव में की गयी थी। वादी ने यह आवेदन पेश करने हेतु झूठा आधार बनाया है कि उसके अधिवक्ता ने उसे कैम्प की सूचना नहीं दी दिनांक 30/06/2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प टूंकडा में वादी के अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर राजस्व वाद को नोटप्रेस में खारिज करवाया है, इसलिए वादी अपने अधिवक्ता के कृत्य से कानूनन पाबन्द है और कानून का भी यह सिद्धान्त है कि अपने अधिवक्ता को जो जानकारी है, वही पक्षकार को भी होती है। वादी का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतु उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नहीं बताया है, इसलिए वादी किसी भी तरह से समय कण्डोन करवाने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। वादी ने दिनांक 11/09/2018 को उक्त वाद खारिज होने की जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर समय माफी हेतु कारण बताया है। इस सम्बन्ध में वादी ने अपने अधिवक्ता से किस दिन सम्पर्क हुआ, दावा खारिज की जानकारी कब हुई तथा किस माध्यम से वादी को जानकारी हुई कोई उल्लेख नहीं किया तथा न ही वादी ने बताया है। इसलिए वादी ने दफा 5 म्याद अधिनियम का जो आवेदन पेश किया है व इसमें जो कारण बताये हैं, वो कानूनन कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है वादी की गौर लापरवाही है। इसलिए उचित व पर्याप्त कारण के अभाव में दफा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे। वादी

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

का यह भी कानूनी कर्तव्य था कि दिनांक 30/06/2016 से दिनांक 11/09/2018 तक के समय की माफी हेतु उचित व पर्याप्त कारण बताना था जो वादी ने नहीं बताया है। इसलिए वादी किसी भी तरह से देरी माफी का हकदार नहीं है। इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आधारों से एवं कानूनी प्रावधानों के तहत वादी किसी भी प्रकार से देरी माफी कण्डोन करवाने का हकदार नहीं है व प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।

प्रार्थी वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी एक विकलांग व गरीब व्यक्ति है, जिसका एक हाथ कटा हुआ है व वादी अक्सर बीमार रहता है तथा वादी के अधिवक्ता ने दिनांक 30.06.2016 को राजस्व कैम्प की कोई जानकारी वादी को नहीं दी एवं न ही वादी राजस्व कैम्प में हाजिर हुआ है एवं वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करके वादपत्र को खारिज करवा दिया। प्रार्थी/वादी द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश कर विलम्ब काल माफ करने का निवेदन करते हुये यह कथन किया है कि वादी अधिवक्ता द्वारा समय पर पत्रावली से सम्बन्धित जानकारी उसको नहीं दी गई और बिना उसकी जानकारी के राजस्व कैम्प में उसकी अनुपस्थिति में हस्तगत वाद को राजस्व कैम्प में नोट प्रेस से खारिज करवा दिया। जिसकी जानकारी वादी को वादग्रस्त आराजी के नकलें प्राप्त करने पर हुई।

अप्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह कथन किया है कि प्रार्थी/वादी का यह कानूनी कर्तव्य था कि वह अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखें तथा अपने वाद की पैरवी हेतु समय-समय पर जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं करना वादी का कानून की निगाह में गौर लापरवाही है, इसलिये वादी स्वयं अपनी लापरवाही का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अप्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के जवाब में प्रार्थी/वादी के कथनों को खारिज करते हुये यह कथन किया है कि वादी ने स्वयं राजस्व कैम्प टूंकड़ा में उपस्थित होकर हस्तगत वाद को अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस करवाया है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एक काशतकार, विकलांग व गरीब व्यक्ति है एवं अधिवक्ता वादी का यह दायित्व है कि वह प्रकरण के संबंध में न्यायालय हाजा की पेशी, दिनांक एवं न्यायालय हाजा में हुई समस्त कार्यवाही की जानकारी अपने मुव्वकील को दें, परन्तु वादी/प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी वकील द्वारा इस सम्बन्ध कोई जानकारी उनको नहीं दी एवं हस्तगत वाद को राजस्व कैम्प में नोट प्रेस से खारिज करवा दिया। प्रश्नगत पूर्व निर्णित मूल वाद की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 30.06.2016 में केवल वादी अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं, वादी के हस्ताक्षर नहीं है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी की अनुपस्थिति में वादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करवाया गया है। प्रश्नगत पूर्व निर्णित मूल वाद वादी द्वारा पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया था तथा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 30.06.2016 को प्रस्तुत हुआ


श्री  
(फास्ट ट्रेक) जेठारण

था तथा लोक अदालत में केवल उभयपक्ष की सहमति से ही प्रकरण निस्तारित किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल अधिवक्ता वादी द्वारा नोट प्रेस कर दिये जाने से वादपत्र को खारिज कर दिया जाना विधिसंगत नहीं माना जा सकता। अतः प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णय के लिये हम वादी पक्षकारान को समुचित अवसर देना आवश्यक समझते हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब के संबंध प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकट कथन एवं परिस्थितियों से हम सहमत हैं, क्योंकि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए न की तकनीकी आधार पर, अतः हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम को स्वीकार करना हस्तगत वाद के सम्यक् न्याय निर्णय में विधिसंगत होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04, व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार करते हुये वादी पक्षकारान को हस्तगत वाद में समुचित अवसर दिया जाना तथा आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाना न्यायासंगत मानते हैं।


### --: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत आदेश-09, नियम-04 एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करते हुये पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। मूल पत्रावली तलब होकर पुनः दर्ज हो।

  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जैतारण  
जैतारण (जिला-पाली)

